MSP लागू कराने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा : राकेश टिकैत

करनाल(जेके शर्मा)। करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी सहित किसान हित के कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर आरोप लगाया कि वह अब धान की खरीद बंद करने जा रही है। सरकार के कागजों में धान की खरीद एमएसपी पर होती है पर किसान की फसल की महज 40 प्रतिशत धान की खरीद एमएसपी पर होती है।

किसान नेता ने कहा कि बड़ा व्यापारी किसानों के नाम पर धान की उपज पूरे दाम पर बेचता है, लेकिन किसान को कई बहाने बना कर खरीद केंद्र से लौटा दिया जाता है ताकि वह मजबूर होकर कम दामों में बड़े व्यापारी को अपनी फसल बेच दे। किसानों के संगठन को मजबूत करने के लिए घोषणा की कि जैसे बीजेपी पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, वैसे हम ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। जब संघर्ष होगा, आंदोलन होगा तो ये ट्रैक्टर प्रमुख ही काम आएंगे। जिस-जिस किसान के पास ट्रैक्टर है उसे प्रमुख बनाया जाएगा। देश भर में जहां-जहां सहकारी समिति है वहां पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जिन जिन बुजुर्गों ने किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी उन्हें संगठन के साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए उनको सम्मानित करने की घोषणा की।

एसवाईएल के मुद्दे पर टिकैत ने राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो ये इसको मुद्दा बनाकर लड़ेंगे ताकि पंजाब हरियाणा में लड़ाई हो। पानी तो काफी है, अटल बिहारी की योजना पर काम होना चाहिए, नहरों को जोड़ने का काम करना चाहिए, बैठकर हल निकालना चाहिए।

सरकार की योजना है कि फसल पूरे भारत में कहीं बेचो तो किसानों को परेशान करते हैं, पोर्टल बना दिया है, लेकिन वो खराब रहता है। एमएसपी लागू होनी चाहिए ताकि किसान को उसकी फसल का दाम मिले। अगर इण्डिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा तो जीत जाएंगे। सरकार बेईमानी करेगी, यूपी में विधानसभा सीटों में कई जगह बेइमानी की है। एमएसपी बड़े आंदोलन से ही लागू होगी, हल्के आंदोलन से नहीं होगी। इसके लिए किसानों को फिर से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।

एफएमडीए : नया नाम रखने से ही नहीं होने लगते सही काम

इस गति से काम करने में तो नीलम-अजरौंदा फ्लाईओवर की मरम्मत में लगा जाएंगे तीन महीने

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। विकास के नाम पर रुपयों की लूट और बंदरबांट करने में माहिर एफएमडीए के थके हुए अधिकारी महज सौ मीटर लंबा नीलम-अजरौंदा पुल भी समय पर नहीं बनवा पा रहे हैं। पहले से बने हुए सौ मीटर लंबे पुल के 22 पिलर और दोनों ओर की सड़क की मरम्मत में दो करोड़ रुपये से अधिक लुटाए जाएंगे लेकिन फिर भी काम लेटलतीफ ही होता जा रहा है। नीलम पुल बंद होने से वाहन चालकों को भी अतिरिक्त ईंधन के रूप में आर्थिक मार सहनी पड़ रही है।

नीलम-अजरौंदा फ्लाईओवर की मरम्मत अप्रैल 2023 में शुरू होने थी लेकिन कभी अतिक्रमण और कभी मौसम का बहाना बना कर काम को टाला जाता रहा। अब एफएमडीए ने दो करोड़ रुपयों में पुल की मरम्मत का प्रोजेक्ट शुरू किया है। यानी मरम्मत के नाम पर प्रति मीटर लभगग दो लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। नीलम पुल नया नहीं बन रहा है बल्कि इसकी मरम्मत की जा रही है। संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि 2020 में भी नीलम पुल के पिलरों की मरम्मत पर करीब पचास लाख रुपये खर्च किए गए थे। तीन साल के भीतर ही एफएमडीए इन पिलरों सहित कुल 22 पिलरों की मरम्मत करवा रहा है। किसी भी निर्माण कार्य के बाद पांच साल तक उसकी देखभाल और मरम्मत का जिम्मा ठेकेदार का होता है लेकिन एफएमडीए के काबिल और ईमानदार अधिकारियों ने पिछले काम को छोड़ते हुए नए सिरे से मरम्मत शुरू करवाई है।

बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश गोयल पुल की मरम्मत में देरी को एफएमडीए द्वारा अक्षम और अयोग्य ठेकेदार को काम दिया जाना मानते हैं। उनके अनुसार कंस्ट्रक्शन और रोड कॉर्पेटिंग की इतनी आधुनिक मशीनें आ गई हैं कि सौ मीटर सड़क चंद घंटे में बन कर तैयार हो जाती है। रही पिलरों की स्ट्रेंथनिंग की बात तो यह काम भी आधुनिक मशीनों के जरिए चंद दिनों में पूरा किया जा सकता है। जब दो करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो ऐसे ठेकेदार को काम देना चाहिए जिसके पास आधुनिक मशीनें हों ताकि चंद दिनों में ही काम पूरा किया जा सके। बेसिक मशीनों से मजदूरों के बल पर काम कराने में तो महीनों लगेंगे ही और खर्च भी ज्यादा होगा। उनका मानना है कि पुल की मरम्मत के बजट की समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है।

एफएमडीए ने पुल की मरम्मत के लिए 44 दिन का समय निर्धारित किया है। इसके तहत पहले 22 दिन में अजरौंदा से नीलम की ओर का ट्रैक बनाया जाएगा, बाकी 22 दिन में नीलम से अजरौंदा की साइड का ट्रैक। 25 सितंबर को काम शुरू हुआ था अभी एक ट्रैक की ओर का केवल साठ प्रतिशत तक ही काम पूरा हो सका है, ऐसे में अंदाज लगाया जा सकता है कि पुल की मरम्मत तीन महीने में भी पूरी नहीं हो सकेगी। इसका खामियाजा वाहन चालकों और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है।

यातायात अधिक होने पर अजरौंदा पर जाम लगता है और दिन भर में हजारों वाहनों का सैकड़ों लीटर ईंधन जाम में फुंक जाता है, इससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। जाम की हालत में बदरपुर से बीके की ओर आने वाले वाहनों को बाटा पुल की ओर डायवर्ट कर दिया जाता है, पहले से ही यातायात की अधिकता से जूझ रहे बाटा पुल पर भी इस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, और वाहनों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगा कर बीके चौक पहुंचना पड़ता है। एफएमडीए अधिकारी शहर और संसाधनों को बर्बाद करने के बाद अब जनता को भी बर्बाद करने में जुटे हैं।

एसीपी ट्रैफिक ने ठेकेदार को धमकाया

नीलम-अजरौंदा पुल की मरम्मत में देरी यातायात पुलिस के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। पुलिस विभाग के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार

एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार ने ठेकेदार को धमकी दी कि अगर 30 अक्तूबर तक पुल नहीं बना तो वह बैरिकेडिंग खोल कर यातायात शुरू करवा देंगे। ठेकेदार ने न तो उनसे पूछ कर काम शुरू किया है और न ही उसने ट्रैफिक रुकवाने या चलवाने के लिए यातायात पुलिस से कहा था, और वह एसीपी ट्रैफिक के प्रति जवाबदेह है।

एसीपी ट्रैफिक यदि सच में पुल की जल्दी मरम्मत करवाना चाहते हैं तो उन्हें एफएमडीए के थके हुए अधिकारियों को लिखना चाहिए। यह लंबा लेकिन कारगर रास्ता एसीपी को भी ठीक नहीं लगा, इसलिए ठेकेदार को धमकाने का शॉर्टकट अपना कर उन्होंने आला अधिकारियों को खुद की कर्मठता बताई। नगर निगम को निकम्मा संस्थान बनाने के बाद एफएमडीए में पहुचे थके और नाकारा अधिकारियों का इतिहास देखते हुए उनसे किसी काम को तय समय सीमा में पूरा करवाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।

सड़क-नालियां चोक कर रहा पुल की रेलिंग का मलबा

नीलम अजरौंदा पुल की रेलिंग भी दोबारा बनाए जाने के लिए तोड़ी जा रही है। मानक के अनुसार तोड़ी गई रेलिंग का निकलने वाला मलबा साथ साथ ट्रक में भर कर हटाया जाना चाहिए। ठेकेदार रेलिंग तुड़वा तो रहा है लेकिन खर्च बचाने के लिए मलबा नहीं भरवा रहा। मलबे को सीधे नीचे फेका जा रहा है जो वहां से गुजर रही नालियों में डंप होकर उन्हें चोक कर रहा है, मलबे के टुकड़े नीचे गुजर रही सड़क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा एवं संरक्षा उपायों के बिना काम करा रहे ठेकेदार को एफएमडीए के अधिकारी भी सुरक्षा मानक के अनुरूप काम कराने को मजबूर नहीं कर पा रहे।

हड़प गए टीबी मरीजों की पोषण.....

पेज एक का शेष

जाती है। जिला टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ. ऋचा बत्रा ने बताया कि यदि किसी मरीज का बैंक खाता नहीं होता है तो उसके पिता, पति, पत्नी, सगे भाई या बहन के खाते में यह धनराशि भेजी जाती है लेकिन इससे पहले लाभार्थी को यह घोषणापत्र देना होता है कि उसकी धनराशि करीबी सगे संबंधी के खाते में भेजी जाए और इस धनराशि का इस्तेमाल वह पौष्टिक भोजन लेने में ही करेगा।

आधार लिंक खाता, सत्यापन आदि औपचारिकताएं होने के बावजूद बीके स्थित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस धनराशि की बंदरबांट कर डाली। सीएम फ्लाइंग की प्रारंभिक जांच में एक ही बैक खाते में विभिन्न टीबी मरीजों की निक्षय पोषण योजना के 31 हजार रुपये ट्रांसफर किया जाना पाया गया। यदि गहराई से जांच की जाती तो सीएम फ्लाइंग को इस तरह के और भी खाते मिलते जिनमें मरीजों की रकम ट्रांसफर कर रुपये हड़पने का खेल किया जा रहा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विभाग में जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कार्रवाई करने के नाम पर सीएमओ डॉ. विनय गुप्ता को रिपोर्ट सौंप कर पल्ला झाड़ लिया गया।

डीएसपी सीएम फ्लाइंग मनीष सहगल का कहना है कि मामला बहुत सारे खातों की जांच करने का था, यह काम ऑडिट टीम ही कर सकती थी, इसलिए सीएमओको जानकारी देकर पूरी जांच कराने का निर्देष दिया था। मनीष सहगल की बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता, कानूनन उन्हें इसकी एफआईआर दर्ज करानी थी, तफ्तीश के दौरान सारे खातों का हिसाब किताब सामने आ जाता। ऐसा न करके उन्होंने मरीजों के हित पर डकैती मारने वाले डकैतों को बड़ी राहत दे दी है क्योंकि सीएमओ ने न तो पहले कभी किसी मामले में कुछ किया है और न कुछ करने की संभावना है। जब भी कोई मामला सामने आता है सीएमओ जांच गठित कर देते हैं जिसका परिणाम सामने आता कभी दिखाई नहीं दिया।

एनआईटी तीन चौकी इंजार्च का कहना है कि सीएमओ ने शिकायती पत्र तो भेजा था इसमें 31 हजार रुपये की रकम एक ही खाते में ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगाया गया था। संबंधित खाता धारक ने यह 31 हजार रुपये वापस तो ही दिए हैं। बावजूद इसके जांच की जा रही है।

सीएमओ डॉ. विनय कुमार ने कहा कि मामले की जांच के लिए डिप्टी सीएमओ डॉ. रामभगत की अध्यक्षता में एक टीम जांच कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा कि 31 हजार रुपये किसके खाते में और कैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसमें जांच करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो सामने है। हां, जांच करने का कोई विषय तो यह हो सकता है कि इस तरह की कितनी डकैतियां हुई हैं जिसे सीएमओ कार्यालय कभी उजागर नहीं करना चाहेगा।

दरअसल, सीएमओ, पुलिस और सीएम फ्लाइंग सभी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही खाते में मरीजों की रकम का भेजा जाना ही साबित करता है कि धनराशि हड़पने का खेल चल रहा था, रकम वापस करवा देने से गुनाह खत्म नहीं हो जाता। जिस तरह पुलिस ने दो सप्ताह बीत जाने के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है उससे नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई होगी। यदि जांच आगे बढ़ी तो गबन की धनराशि किन अधिकारियो तक बंटती थी यह भी सामने आएगा जिसमें कई बड़े अधिकारियों की गर्दन भी फंसने की संभावना हो सकती है, ऐसे में हड़पी रकम वापस करवा कर मामले पर पर्दा डालने के प्रयास किए जा रहे हैं।